तमिलनाडु की तर्ज पर यूपी में चमड़ा उद्योग के लिए बनेगी नीति

लेदर और नॉन लेदर फुटवियर की बढ़ रही मांग, रोजगार-व्यापार की व्यापक संभावना, यूपी के कारोबारी बोले- सरकार साथ दे तो तमिलनाडु से बड़ा हब बना देंगे

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। निर्यात और रोजगार के नजरिये से सबसे लाभकारी उद्योगों में से एक लेदर व फुटवियर सेक्टर पर केंद्र की मेहरबानी के बाद राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण नीति लाने की तैयारी में है। एमएसएमई विभाग नीति तैयार करेगा। इसके तहत लेदर व फुटवियर इकाइयों को वित्तीय सहायता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए प्रोत्साहन राशि व निर्यात संवर्धन में मदद का खाका तैयार किया जाएगा। इससे प्रदेश के चमड़ा उद्योग में अगले पांच साल में 100 फीसदी के वृद्धि का अनुमान है।

लेदर और नान लेदर फुटवियर की मांग साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यदि भारत में ही प्रति व्यक्ति एक जोड़ी फुटवियर बढ़ा तो 140 करोड़ फुटवियर की मांग अतिरिक्त होगी। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति फुटवियर 3 से भी कम है। वहीं, यूरोप में ये 8 और अमेरिका में 9 फुटवियर प्रति व्यक्ति है।

इस उद्योग से रोजगार और व्यापार की व्यापक संभावना को देखते हुए राज्य सरकार पहली बार एक नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत डिजाइन कैपिसिटी, कंपोनेंट निर्माण, मशीनरी और कुशल कार्यबल को तैयार किया जाएगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु की तर्ज पर फुटवियर व लेदर नीति तैयार की जा सकती है। मौजूदा लेदर क्लस्टर्स आगरा, कानपुर, उन्नाव और नोएडा में वित्तीय व तकनीकी मदद के लिए इकाइयों को चिह्नित किया जाएगा।

प्रदेश की जरूरतें और क्षमताएं

- यूपी में फुटवियर इंडस्ट्री के लिए जमीन वहां मिले, जहां हाईवे और एक्सप्रेस्वे करीब हो।
- ऐसी जगह मिलें, जहां श्रमिक, कर्मचारी के साथ अधिकारी भी रह सकें
- नोएडा की तरह अच्छे शहरों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए
- लेबर ट्रेनिंग में मदद चाहिए। ट्रेनिंग खर्च में सरकार मदद करे।

सरकार से सिर्फ सहयोग व सस्ती जमीन चाहिए : अमीन

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के सदस्य व चर्म निर्यात परिषद के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि लेदर इंडस्ट्री को सिर्फ सरकार से सहयोग और सस्ती जमीन चाहिए। कुशल कामगारों का प्रशिक्षण चाहिए। यहां के उद्यमी तमिलनाडु से बड़ा लेदर क्लस्टर यूपी में बनाकर दिखा देंगे। तमिलनाडु सिर्फ सस्ती जमीन के दम पर 12 हजार करोड़ का विदेशी निवेश ला चुका है। अमेरिका द्वारा चीन पर 10 फीसदी ड्यूटी बढ़ाने का फायदा भारत को मिल सकता है। कीमत के मोर्चे पर भारत को फायदा मिलेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ बल्क सप्लाई का मोर्चा चुनौतीपूर्ण है।

यूपी में तमिलनाडु से ज्यादा क्षमता : जालान

चर्म निर्यात परिषद के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि राज्य सरकार थोड़ी सी मदद कर दे तो यूपी में 300-300 एकड़ के दो लेदर पार्क लग जाएंगे। यहां नॉन लेदर और लेदर फुटवियर सहित अन्य उत्पाद बनेंगे। यूपी में तमिलनाडु से ज्यादा क्षमता है। यूपी में सक्षम व कुशल कार्यबल है, लेकिन यहां से फुटवियर लेबर तमिलनाडु जा रहा है। अनुशासन और कानून व्यवस्था भी यूपी की सबसे अच्छी है।

तमिलनाडु में निवेश के कारण

तमिलनाडु में जमीन सस्ती होने से विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। कैपिटल सब्सिडी, ओवरहेड सब्सिडी, मार्केटिंग और ट्रेनिंग में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान वहां भारी निवेश के मुख्य कारण हैं।